RNI No. 46148/86 भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पो० रजि० नं० J/RA.N.P-5

जनछाया

युवा क्रांति का सशक्त साप्ताहिक

उत्तर प्रदेश शासन तथा भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

सम्पादक : घनश्याम मिश्र ♦ WWW.JANCHHAYA.IN ♦

वर्ष : 35 अंक : 01 मुँगराबादशाहपुर जौनपुर, शुक्रवार 27 दिसम्बर 2019 तक पृष्ठ : 8 मूल्य : 1 रुपया

अ्र में उपद्रवियों को भेजा वसूली का नोटिस

सख्ती : नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों पर पहली बड़ी कार्रवाई

लखनऊ संवाददाता। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध की आड़ में हुई ोहसा पर उपद्रवियों की शिनाख्त और धरपकड़ में तेजी आई है, बल्कि नुकसान के आकलन के बाद वसूली की दिशा में

उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। न केवल भी पुलिस–प्रशासन ने कदम बढ़ा दिए हैं। इस मामले में पहली बड़ी कार्रवाई रामपुर में सामने आई है, जहां बवाल में हुए 17 लाख के नुकसान की भरपाई के लिए 28 आरोपितों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसी तरह लखनऊ सहित अन्य स्थानों पर भी बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। रामपुर में हुई ोहसा के दौरान सरकारी संपत्ति को 17 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। इसकी वसूली के लिए प्रशासन ने उन 28 लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जो जेल भेजे जा चुके हैं। जेल में ही इन्हें नोटिस तामील कराई जाएगी। नोटिस में आरोपितों से अपनी सफाई में साक्ष्य पेश करने के लिए कहा गया है। यदि इनका जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो प्रशासन इनसे वसूली करेगा। धनराशि जमा न करने पर इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और फिर नीलाम की जाएगी।

इसके अलावा पुलिस ने शहर में जगह–जगह उपद्रवियों के पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। इसमें बवाल करते लोगों के फोटो हैं। रामपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डा. अजय पाल शर्मा ने बताया कि वीडियो फुटेज से भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस धरपकड़ के लिए दबिश भी दे रही है।

लखनऊ में अब तक 110 लोगों को नोटिस रू लखनऊ को ोहसा की आग में झोंकने वाले 110 लोगों को अब तक नोटिस जारी किया गया है। एडीएम ट्रांस गोमती विश्व भूषण मिश्र के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं, जो क्षेत्रवार हुए नुकसान का मूल्यांकन कर रही हैं। हिंसा और उपद्रव में यहां करीब पांच करोड़ की निजी और सरकारी संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। अभी तक तक केवल मदेयगंज में ही तहसील प्रशासन ने करीब 27 लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया है।

संभल में 26 लोगों को नोटिस, अमरोहा व गोरखपुर में भी कड़ाई रू संभल में भी नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी (डीएम) अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि अभी तक हिंसा और आगजनी के मामले में चिह्नित किए गए 26 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस उनके घरों पर चस्पा किए जा रहे हैं। 43 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमरोहा में 28 उपद्रवियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी हुए हैं। गोरखपुर में पत्थरबाजी के मुकदमे में फरार चल रहे 33 नामजद आरोपितों के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं। गुरुवार तक बयान दर्ज न कराने पर कुर्की होगी। वहीं बिजनौर के नहटौर में ोहसा में चार दिन बाद थानेदार नप गए हैं। मुकदमों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित की गई है। पुलिस ने जिलेभर में सौ से अधिक बवालियों को चिन्हित किया है। यहां अब तक 146 गिरफ्तारी हुई है।

अटल भूजल योजना लांच,15 करोड़ घरों को नल से जल

नई दिल्ली । अगले पांच सालों में ग्रामीण क्षेत्रों के 15 करोड़ घरों में नल से जल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। जल से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को पूरा करने में कुल साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल से जुड़े बड़े फैसलों का एलान करते हुए कहा, 'जल संकट से देश का विकास प्रभावित होता है।' उन्होंने किसानों और महिलाओं से पानी की बर्बादी रोकने की अपील करते हुए कहा, 'तकनीक के जरिये कृषि समेत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पानी बर्बाद होने से बचाया जा सकता है।' मोदी बुधवार को यहां अटल जयंती पर आयोजित एक समारोह में अटल भूजल योजना का शुभारंभ करने के बाद बोल रहे थे। अटल भूजल योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक के 78 जिलों में चलेगी, जिसका लाभ वहां के 8350 गांवों को मिलेगा। मोदी ने कहा, इस योजना पर 6000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें तीन हजार करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी, तीन हजार करोड़ रुपये विश्व बैंक से प्राप्त होंगे। योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल स्तर ऊपर उठाने का है, जिन इलाकों में यह बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। इससे जहां कृषि क्षेत्र का भला होगा, वहीं लोगों को अच्छे पेयजल की आपूर्ति में मदद मिलेगी। अटल भूजल योजना की सफलता के बारे में मोदी ने कहा, इसका सारा दारोमदार पंचायतों पर है। इनके लिए स्थानीय स्तर पर ही जल समितियां बनेंगी। उन्होंने स्टार्टअप के लोगों से उम्मीद जताई कि वे ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करें जिससे कम पानी में ज्यादा काम हो सके। कहा, ध ाान व गन्ने की खेती में बहुत पानी लगता है। इसमें माइक्रो इरिगेशन का उपयोग होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, 'न्यू इंडिया को हमें जल संकट की हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना है। इसके लिए हम पांच स्तर पर एक साथ काम कर रहे हैं। पानी से जुड़े कई विभागों को एक साथ जोड़कर एक जलशक्ति मंत्रलय बनाया गया है। विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं को एक साथ किया है। उपलब्ध जल के साथ संचयन व वितरण पर जोर है। पानी के कम उपयोग से अधिक काम और गंदे पानी की रिसाइकीलिंग को प्रमुखता दी गई है। जल के प्रति जागरूकता और जनभागीदारी पर विशेष बल दिया जा रहा है।' उन्होंने कहा, एक तरफ 'जल जीवन मिशन' है, जो हर घर तक पाइप से जल पहुंचाने का काम करेगा और दूसरी तरफ 'अटल जल योजना' है, जो उन क्षेत्रों पर विशेष ध यान देगी जहां ग्राउंड वॉटर बहुत नीचे है। इसीलिए जल से संबंधित योजनाओं को पूरा करने पर केंद्र व राज्य सरकारों को मिलाकर कुल साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। मोदी ने कहा, गत 70 वर्षो में सिर्फ तीन करोड़ ग्रामीण घरों में ही पाइप से पानी की आपूर्ति हो पाई है। अगले पांच सालों में 15 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जलापूर्ति की जाएगी।

जय बजरंग महिला इण्टर कालेज
मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर
आवश्यकता है

जय बजरंग महिला इण्टर कालेज ,मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर में कला एवं विज्ञान वर्ग के विषयों में प्रवक्ताओं की। तथा गैर शैक्षणिक में 2 पद कम्प्यूटर आपरेटर 1 पद। योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद के नियमानुसार। आवेदन सादे कागज पर 2 फोटो एवं समस्त शैक्षणिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति विद्यालय में भेजे। महिला आवेदकों को वरीयता।

मो0–9451117446 डॉ. घनश्याम मिश्र
संस्थापक / प्रबन्धक

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने दिया इस्तीफा

रांची । झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। गिलुवा ने इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भेज दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं इस पर निर्णय अब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और इसी को आधार बना मैंने इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। यह भी कहा कि उन पर इस्तीफे का कोई दबाव नहीं था। गिलुवा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार की समीक्षा को लेकर जल्द ही बैठक होगी। कहां कमी रही इस पर मंथन होगा ताकि आगे उन गलतियों को सुधारा जा सके। कहा, हम चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा है। पार्टी जनता के बीच जाकर निरंतर अपना काम करती रहेगी। भितरघात पर कहा कि कुछ सीटों पर भितरघात हुआ है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। कुछ अपने लोगों ने ही ऐसा किया, समीक्षा के दौरान इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आजसू की डिमांड कुछ ज्यादा थी रू उन्होंने स्वीकारा कि आजसू से गठबंधन न होने का खामियाजा दोनों ही दलों को भुगतना पड़ा है। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और ही होता। गठबंधन क्यों नहीं हो सका पर कहा कि अब चुनाव बीत गया है, इस पर टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उनकी डिमांड कुछ ज्यादा थी। पिछले चुनाव में उन्हें आठ सीटें दी गईं थी, इस बार 12 दी जा रहीं थी, लेकिन वे इससे कहीं अधिक की डिमांड कर रहे थे।

बीमा एजेंट लूटकांड : एक आरोपित ने किया सरेंडर

मोहनलालगंज–लखनऊ (संवाददाता)। कस्बे के डायमण्ड रिसोर्ट से दस माह पहले एक बीमा एजेंट व उनके कार चालक को फार्चूनर सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा लूटने के मामले में एक आरोपित ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उल्लेखनीय है कि उक्त रिसोर्ट परिसर से बीमा एजेंट व उनके कार चालक का अपहरण कर अतरौली गांव के बाहर स्थित एक सूनसान मकान में बंधक बनाकर पीटा और दो मोबाइल फोन सहित सोने की चेन व ब्रसलेट लूट लिया था। बीमा एजेंट दीपक कुमार पाण्डेय निवासी साउथ सिटी ने मोहनलालगंज कोतवाली में तहरीर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध फार्चूनर के नम्बर के आधार पर दी थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्तकी गयी फार्चूनर के नम्बर के आधार पर एक बदमाश नरेन्द्र प्रताप सिहं उर्फ गोलू सिहं निवासी अतरौली की पहचान होने के बाद से मोहनलालगंज पुलिस आरोपित कि धरपकड़ के प्रयास में जुटी थी लेकिन आरोपित पुलिस के हत्थे नही चढ़ रहा था। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय से आरोपित के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू लेने के साथ ही घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया तो घबराये बदमाश गोलू सिंह ने 18 दिसम्बर को न्यायालय में समर्पण कर दिया। इंस्पेक्टर जीडी शुक्ला के निर्देश पर विवेचक बलवीर सिंह ने न्यायालय में आरोपित को पुलिस कस्टडी रिमांड दिए जाने की याचना की, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर जिला कारागार में बंद आरोपित गोलू सिंह को को मोहनलालगंज पुलिस को नौ घंटे की रिमाण्ड पर दिया गया, जिसके बाद पुलिस अभिरक्षा में आरोपित को विवेचक सहित पुलिस टीम कोतवाली लाकर कड़ाई से पुछताछ कर उसकी निशानदेही पर बीमा एजेंट से लूटा गया एक नोकिया एनरायड मोबाइल फोन व एक वीवो का मोबाइल फोन, पीड़ित का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो अतरौली गांव के बाहर झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था, उसे बरामद कर लिया। वहीं आरोपित ने पूछताछ में घटना में शामिल अपने साथियों द्वारा बीमा एजेंट से लूटी गयी सोने की चेन, ब्रेसलेट व अंगूठी बेचने की बात कही है। मोहनलालगंज इंस्पेक्टर जीडी शुक्ला ने बताया पीसीआर पर लिए गये बदमाश गोलू सिंह ने घटना में शामिल अन्य आरोपितो के नाम बताये हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गये हैं।

मोहनलालगंज को नपं का दर्जा मिलने से खुशी की लहर

मोहनलालगंज (संवाददाता)। पिछले कई वर्षो से मोहनलालगंज को नगर पंचायत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास को सफल साबित हो गए। आखिकर कैबिनेट ने मोहनलालगंज को नगर पंचायत बनाने को हरी झंडी दे दी। सूचना मिलने ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मिठाई बांटकर व आतिशबाजी चलाकर जश्न मनाया।मोहनलालगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने की बीते कई वर्षो में ग्रामीणो द्वारा उठायी गयी मांग के क्रम में तीन साल पहले मोहनलालगंज के तत्कालीन उपजिलाधिकारी नंद लाल सिंह ने की थी। चयन की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसके लिए मोहनलालगंज, मऊ, अतरौली ,डेहवा,गौरा सहित इसके सभी मजरो को शामिल करने पर सहमति बनी।जिसके बाद तत्कालीन एसडीएम नंद लाल सिंह ने मोहनलालगंज को नगर पंचायत का दर्ज दिये जाने का प्रस्ताव बनाकर तत्कालीन जिलाधिकारी राजशेखर के जरिये शासन को भिजवाया था लेकिन शासन में मोहनलालगंज को नगर पंचायत का दर्ज दिये जाने की फाइल लम्बित हो गयी थी।तीन साल पहले भाजपा सरकार बनने के बाद से सांसद कौशल किशोर सहित यूपीसीएलडीएफ चौयरमैन वीरेन्द्र कुमार तिवारी ने नगर विकास मंत्री सहित मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मोहनलालगंज को नगर पंचायत दिलाये जाने की कई बार मांग की तो वही सपा विधायक अम्ब्रिश पुष्कर ने विधानसभा सत्र में मोहनलालगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने की आवाज उठायी थी जिसके बाद मगंलवार को कैबिनेट की बैठक में मोहनलालगंज को नगर पंचायत बनाने की मंजूरी पर मुहर लगा दी। मोहनलालगंज को नगर पंचायत का दर्जा मिलने की जानकारी मिलते ही लोगो में खुशी की लहर दौड़ गयी जिसके बाद कस्बे में इकट्ठा हुये लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व अतिशबाजी छोड़कर खुशी का इजहार किया।

नाका गुरुद्वारे में शहीदी पर्व पर हुआ शबद कीर्तन

लखनऊ (संवाददाता)। माता गुजरी सत्संग सभा की ओर से साहिब श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों, उनकी माता, माता गुजर कौर एवं गुरुजी के लाडले सिंहों का शहीदी दिवस गुरू सिंह सभा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हिन्डोला में बड़ी श्रद्धा एवं सत्कार के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर को दीवान रहिरास साहिब के पाठ से आरम्भ हुआ जो रात्रि 10.00 बजे तक चला जिसमें रागी जत्था भाई राजिन्दर सिंह ने सूरजि किरणि मिलै जलु का जल हुआ राम शबद कीर्तन गायन किया। विशेष रूप से पधारे रागी जत्थे बीबी जसप्रीत कौर जी खालसा लुधियाना वालों ने–ऐसी मरनी जो मरै बहुरि न मरना होइ शबद कीर्तन गायन कर समूह संगत को निहाल किया। रागी जत्था भाई कमलजीत सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर वालों ने अपनी मधुरवाणी में पहिला मरणु कबूलि जीवन को छड़ि आस। होहु सभना की रेणुका तऊ आऊ हमारे पासि शबद कीर्तन गायन कर समूह संगत को भाव विभोर किया किया।दीवान की समाप्ति के उपरान्त लखनऊ गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष स0 राजेन्द्र सिंह बग्गा जी ने चारो साहिबजादों एवं माता गुजर कौर एवं गु जी के लाडले सिंहों की शहादत को नमन किया। मंच का संचालन सतपाल सिंह मीत ने किया। अरदास के उपरान्त गुरू का लंगर श्रद्धालुओं में वितरित किया गया।

सभ्य समाज के निर्माण में सहायक हैं स्कूल : नाईक

लखनऊ(संवाददाता)। विद्यालय वह स्थान है, जहां सभ्य समाज का निर्माण होता है। यह बात को जानकीपुरम स्थित ठाकुर पब्लिक स्कूल के भवन का लोकार्पण के दौरान प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने कहीं। उन्होंने ठाकुर पब्लिकेशन की पुस्तकों की सराहना की। इस मौके पर पूर्व राज्यपाल ने ठाकुर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित लखनऊ विविद्यालय के बीकॉम की पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही साथ पुस्तक के लेखक डॉ अजय प्रकाश, डॉ अवधेश कुमार, डॉ अजय शुक्ला व सुरेश चंद्र अग्रवाल को सम्मानित किया। इस मौके पर गाइड समाज कल्याण संस्थान की निदेशक डॉ इंदु सुभाष ने कहा कि कि हमारे प्रत्येक कार्य में सभी की भलाई की भावना निहित होनी चाहिए। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुधीर कुमार वर्मा व मेजर वी के खरे, रघुवंश ठाकुर, मनोज कुमार ठाकुर, श्रीमती वीरा करोली, निधि, सास्वत, देश दीपक राजपूत, उषा नेगी, सौमित्र वीर सिंह, राजकुमार सिंह, प्रवेश कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, तृप्ति चौधरी व रवि प्रकाश मौजूद थे।

प्रदेश के पांच लाख व्यापारियों पर लटकी जुर्माने की तलवार

लखनऊ (संवाददाता)। नागरिक संशोधन बिल के बाद फैली अशांति के साथ ही आर्थिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। माल की आवक तो बन्द ही है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के करीब पांच लाख व्यापारियों पर जुर्माने की तलवार भी लटक गयी है, जिनका मुख्यकारण इन्टरनेट सेवाओं का बंद होना है। हालात ये है कि एक तरफ व्यापारी जुर्माने को लेकर भयभीत हैं, वहीं माल की आवक बंद होने से काम–काज भी ठप होता नजर आ रहा है। जीएसटी में टैक्स व रिटर्न जमा करने की अन्तिम तिथि 20 दिसम्बर थी, लेकिन 19 दिसम्बर की रात को ही इन्टरनेट बंद हो जाने से बहुत से व्यापारी जीएसटीएन पोर्टल पर रिटर्न व टैक्स नहीं जमा कर सकें। इसके चलते ऐसे व्यापारी जिनको शून्य रिटर्न यानी कोई खरीद‍ बिक्री नहीं की उन पर 10 रूपये प्रतिदिन और जिन व्यापारियों ने कारोबार किया है और टैक्स की देनदारी बनती है, उन पर ₹ 50 प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स की देनदारी बन गयीं। व्यापारियों के दबाव के बाद सरकार ने 23 तारीख तक के लिए तिथि बढ़ दी। को भी नेटबंद हो जाने से एक बार फिर सेवाएं बाधित हो गयीं , जिससे व्यापारी रिटर्न दाखिल करने से वंचित रह गये और प्रदेश के पांच लाख व्यापारियों पर एक बार फिर जुर्माने की तलवार लटक गयी।माल की आवक ठप रू जीएसटीएन पोर्टल बंद होने से व्यापारी माल के परिवहन के लिए ई–वेबिल नही डाउन लोड कर पाए, इसके चलते माल की आवक यूपी में बहुत कम हो गयी है। हालत ये हो रही है कि सीमेन्ट, मौरंग, लोहा जैसे उत्पाद जिनकी लगातार खपत होती है, उनके ट्रक भी यूपी में नहीं आ पा रहे हैं जिसके कारण परियोजनाओं में काम प्रभावित हो रहा है।

गरीबों व बेसहारों को भोजन उपलब्ध कराना लक्ष्य : नवीन आस्था

लखनऊ (संवाददाता)। रोटी बैंक सेवा संस्थान की अध्यक्ष नवीन आस्था शुक्ला ने कहा है कि गरीबों, बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराना ही उनकी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर उनकी संस्था सप्ताह में एक दिन गरीबों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराये जाते है। इस पैकेट में चार रोटियां, सब्जी, फल व मिष्ठान शामिल होता है। श्रीमती शुक्ला को राजाजीपुरम में बालाजी मंदिर में सड़क के किनारे गरीब बुजरुगों व मलिन बस्तियों में बेसहारा बच्चों को भोजन वितरण के समय कहीं। इस अवसर पर उन्होंने करीब दो सौ गरीब बुजरुगों महिलाओं व बच्चों को भोजन के पैकटों का वितरण कराया। रोटी बैंक सेवा संस्थान के सदस्यों ने को पहले भोजन के पैकटों का मिलकर तैयार किया तत्पश्चात बालाजी हनुमान मंदिर व हैदरकैनाल नाले के किनारे बसी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बेसहारा बच्चों व महिलाओं को भोजन के पैकटों का वितरित कराया। इस अवसर पर राजाजीपुरम स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में जाकर मरीजो व तीमारदारों को भोजन के पैकेटों का वितरण कराया। इन पैकेटों में रोटी सब्जी, फल व मिष्ठान शामिल था। इस अवसर पर नवीन आस्था शुक्ला, सुनीता शुक्ला, अंशिका शुक्ला, गीता सौमानी, ज्योत्सना श्रीवास्तव, सोनी रावत, अनुभा, कोमल, लता, पप्पू मालवीय, यशार्थ शुक्ला, धर्मा पाल, विवके दुग्गल,, नीशेष यादव, ऋषि तिवारी, वर्णित शुक्ला, अभिषेक पांडे, मानस दीक्षित, मुकेश वर्मा, विशाल मिश्रा गौरव आदि तमाम लोग मौजूद थे।

पाल समाज को एकजुट करना जरूरी : महादेव

लखनऊ (संवाददाता)। प्रदेश के पूर्वमंत्री महादेव जानकर ने कहा है कि पाल समाज को एकजुट करना जरुरी है। उन्होंने कहा कि जब तक पाल समाज एकजुट नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकता। पूर्वमंत्री को खरिका वार्ड के तेलीबाग स्थित लौंगा खेड़ा में पूर्व पार्षद प्रत्याशी मनोज कुमार पाल के आवास पर आयोजित समाज के प्रति चिंतन बैठक में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में समाज को एकजुट व शिक्षा के प्रति जागरुक होने पर जोर दिया। चिंतन बैठक में पूर्व मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल ने कहा कि पाल समाज अति पिछड़ी जातियों में आती है लेकिन यह समाज ने हमेशा संघर्ष को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पाल समाज मुख्य पेशे से दूर हटता जा रहा है इसका प्रमुख कारण प्रदेश सरकारों द्वारा इस समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके पाल समाज को बढ़ाने का काम नहीं किया। यहीं कारण है कि पाल समाज लगातार नीचे गिरता गया और शिक्षा से भी दूर होता गया। चिंतन बैठक में पूर्व विधान परिषद सदस्य प्रभावती पाल, जानकी पाल, प्रतापगढ़ के विधायक राज कुमार पाल,, पूर्व जिलापंचायत सदस्य गोविंद पाल, उप्र अहिल्या बाई होल्कर सेवा संस्थान के अध्यक्ष गुरु प्रसाद पाल, मनोज कुमार पाल,आरएस पाल, प्रधान राजकुमार पाल, भगीरथ पाल, दिनेश पाल, सपा युवा नेता सुनील पाल, सुरेश पाल, संदीप पाल समेत पाल समाज के तमाम लोग मौजूद थे।

'मील ऑन रोड`' का तोहफा

लखनऊ (संवाददाता)। अब सफर के दौरान ही यात्री अपनी फेवरेट डिश का आर्डर कर सकेंगे तथा यात्री प्लाजा पर पहुंचते ही उनकी फेवरेट डिश उन्हें मिल जाएगी। इसके लिए रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को परिवहन निगम ने ''मील ऑन रोड' का तोहफा दिया है। इससे यात्रियों को खाने के लिए घंटो इंतजार नहीं करना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में को ''मील आन रोड' ऐप की शुरुआत की गयी। इस एप के माध्यम से रोडवेज की बसों में सफर के दौरान यात्री परिवहन निगम से अनुबंधित प्लाजा और ढाबों पर अपनी मनचाही डिश आर्डर कर सकेंगे। गूगल प्ले पर जाकर कोई भी व्यक्ति यह ऐप डाउन लोड कर सकता है। ऐप पर जाते ही आगे आने वाले प्लाजा पर उपलब्ध डिशेज का ब्योरा (मीनू कार्ड) सामने आ जाएगा। इसके बाद यात्री अपनी मनपसंद डिश का चयन कर सकता है। इसके बाद उसे अपने बस का नम्बर, यात्रा की तारीख और मार्ग डालने पर उसका आर्डर बुक हो जायेगा। इस ऐप में प्रदेश के लगभग 40 फूड प्लाजा और अनुबंधित ढाबे का ब्योरा सामने आएगा, जिन रूटों पर इनकी व्यवस्था है वहां के लिए लगभग दो हजार बसों का संचालन हो रहा है, ऐसे में प्रतिदिन 70 हजार यात्रियों को इस ऐप का लाभ मिल सकेगा। यात्री इस एप के माध्यम से अपना फीड बैक और सुझाव भी दे सकेंगे। ऐसे में खराब खाने की सूचना मिलने पर परिवहन निगम संबंधित यात्री प्लाजा के खिलाफ एक्शन लेगा। इसके साथ ही एप ड्राइवरों की मनमानी पर भी अंकुश लगाएगा। वे मनचाहे प्लाजा पर बस नहीं रोक सकेंगे, परिवहन निगम से अनुबंधित प्लाजा पर ही बसें रोक सकेंगे। यहां यात्रियों को उचित दरों पर अच्छा खाना मिल सकेगा। परिवहन निगम के एमडी डा. राज शेखर ने को ''मील आन रोड' एप का शुभारम्भ किया।

मर्चेन्ट नेवी में नौकरी के नाम पर ठगे 10.60 लाख

लखनऊ (संवाददाता)। पंजाब कॉलेज ऑफ मरीन आफिसर में दाखिला और फिर मर्चेन्ट नेवी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर जालसाज ने दो छात्राओं से 10.60 लाख रुपये ऐंठ लिए। जालसाज ने कॉलेज में छह माह की जगह तीन माह का कोर्स कराकर सर्टिफिकेट थमा दिया। नौकरी के नाम पर टालमटोल होने पर छात्राओं ने पड़ताल की तो पता चला कि सर्टिफिकेट जाली हैं। ठगी का एहसास होने पर दोनों ने रुपये वापस मांगे तो आरोपित ने टालमटोल की। गोमतीनगर पुलिस ने दो मुकदमें दर्ज कर लिए हैं।इंस्पेक्टर गोमतीनगर अमित कुमार दुबे ने बताया कि बड़ी जुगौली गोमतीनगर निवासी मानसी यादव व गोसाईगंज के निजामपुर निवासी सोनिया कनौजिया एक ही कालेज में पढ़ती थी। वर्ष 2017 में कालेज के एक कार्यक्रम में गोमतीनगर के विरामखण्ड–5 निवासी प्रशांत सिंह आए थे। कार्यक्रम में छात्रा मानसी व सोनिया की प्रशांत से मुलाकात हुई। दोनों का कहना है कि प्रशांत ने पंजाब के रोपण स्थित पंजाब कॉलेज ऑफ मरीन आफिसर कोर्स में दाखिला दिलाने की बात कही। इसके बाद प्रशांत ने दोनों का दाखिला कराने के नाम पर 5.50 लाख रुपये ऐंठ लिए। प्रशांत ने दोनों छात्राओं को छह माह का कोर्स होने की बात कही थी। छात्राओं का कहना है कि रुपये लेने के बाद प्रशांत ने उनका दाखिला करा दिया। मार्च 2018 से लेकर जुलाई माह तक का कोर्स कराया। तीन माह में कोर्स पूरा होने की बात कहकर जालसाज ने दोनों को सर्टिफिकेट थमा दिया। इसके बाद मानसी व सोनिया वापस लखनऊ लौट आयी। उनका कहना है कि कोर्स पूरा होने के बाद जालसाज प्रशांत ने मर्चेन्ट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे 6.10 लाख रुपये लिए। रुपये देने के बाद भी छात्राओं को नौकरी नहीं मिली। शक होने पर पीड़ित छात्राओं मानसी यादव व सोनिया कनौजिया ने पड़ताल की तो प्रशांत के फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। पता चला कि जालसाज प्रशांत ने उन्हें जो सर्टिफिकेट दिये थे, वह भी जाली हैं।

सीडीआरआई व सिप्ला में समझौता

लखनऊ (संवाददाता)। केन्द्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई) तथा दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने देश की स्वास्य सेवाओं के सुधार, विकास तथा विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए आवश्यक उन्नत दवाओं के विकास एवं उपलब्ध दवाओं के पुनरू उपयोग के माध्यम से नई दवाओं के विकास का लिए एक परस्पर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान सीडीआरआई के निदेशक डा. तपस कुण्डू ने कहा कि सीडीआरआई देश का प्रीमियर ड्रग डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट है। इसके लिए यह शानदार क्षण है, जब वह सिप्ला जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सहयोग और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सर्वसुलभ एवं सस्ती स्वास्य सेवा के अपने मिशन की पूर्ति के लिए न केवल भारत के लिए बल्कि नियंतण्र बाजारों के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी संस्थान तथा फार्मास्युटिकल उद्योग की भागीदारी का एक अनूठा प्रयास है, जो इस देश में विकसित सर्वसुलभ व सस्ती स्वास्य सेवाओं को दुनियाभर में मुहैया करवाने का प्रयास करेगा। सिप्ला के डा. वाई.के. हामिद ने कहा कि सीडीआरई के साथ सिप्ला का जुड़ाव वर्ष–1942 से चल रहा है तथा सिप्ला, सीडीआरआई और आईआईसीटी की प्रयोगशालाओं में विकसित विशेषज्ञताओं से वर्षो से लाभ ले रहा है। अतीत में सीडीआरआई की दो विभूतियां डा. नित्या आनन्द तथा डा. ए.वी. रामाराव सिप्ला के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। अब सीडीआरआई व सिप्ला न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर नई दवाओं के विकास के लिए एक भविष्य के कार्यक्रम पर विचार रहे हैं। उम्मीद है कि इस भागीदारी के आगामी परिणाम बेहतरीन होंगे।

कम प्लेटलेट्स का तत्काल चलेगा पता

लखनऊ (संवाददाता)। एक लाख लोगों में से पांच से सात लोगों को प्लेटलेट्स की समस्या होती है। काफी समय पहले इन पांच से सात मरीजों की मौत हो जाती थी, क्योंकि प्लेटलेट्स की जांच के लिए पहले उच्च तकनीक नहीं थी। अब नई तकनीक से मरीज के कम प्लेटलेट्स होने की जानकारी तुरंत हो जाती है। यह जानकारी को डा. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में डा. सुब्रत चंद्रा ने दी। इम्यून रोम्बोसाइटोपेनिया विषय पर सीएमई (सतत चिकित्सा शिक्षा) में विभाग के प्रमुख डा. सुब्रत चंद्रा ने बताया कि रोम्बोसाइटोपेनिया ऐसी बीमारी है, जिसमें प्लेटलेट्स सामान्य से काफी कम हो जाती है। यह एनिमिया के बाद रक्त का सबसे सामान्य रोग माना जाता है, जोकि पुष व महिला को समान रूप से होता है। खून का थक्का बनने की प्रक्रिया में प्लेटलेट्स की अहम भूमिका होती है। यदि किसी व्यक्त को खून में थक्का बनने की दूसरी बीमारी हो तो यह और जानलेवा हो सकती है। ल्यूकेमिया की होती है। दिक्कत रोम्बोसाइटोपेनिया एक अलग बीमारी के रूप में सामने आता है, जैसे ल्यूकेमिया या इम्यून सिस्टम में कमी। प्लेटलेट्स की कमी के अलावा बार–बार चोट लगना, त्वचा में सतही रक्तस्रव हो जाना, हल्की खरोंच या चोट लगने पर देर तक खून बहना, मसूड़े या नाक से खून आना, पेशाब या मल में खून आना, मासिक धर्म में असामान्य रक्तस्रव होना। लोहिया संस्थान के निदेशक डा. एके त्रिपाठी, डा. केके यादव, डा. कीर्ति, डा. विक्रम सिंह, पीजीआई, केजीएमयू आदि जगह से चिकित्सक मौजूद थे।

नेपाली मरीजों को सस्ते इलाज का झांसा देकर लाने पर स्वास्य विभाग सख्त

लखनऊ (संवाददाता)। निजी अस्पतालों ने बेहतर व सस्ते इलाज का झांसा देकर नेपाल सेआये मरीजों की खरीद–फरोख्त सिंडिकेंट बना रखा है। इनके दलाल भारत–नेपाल बार्डर तक फैले हुए हैं। मरीजों को बेहतर सस्ता इलाज का झांसा देकर निजी अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां नेपाली मरीजों से अवैध वसूली होती है। पए का भुगतान न कर पाने पर नेपाली मरीजों को बंधक बनाए जाने के कई मामले सामने आए हैं। निजी अस्पतालों के इस सिंडिकेंट को तोड़ने के लिए स्वास्य विभाग ने तैयारी की है। स्वास्य विभाग ने नेपाली मरीजों की सूची तैयार कराएगा। जिसके बाद उसको पुलिस को देकर दलालों पर रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी। नेपाल की निशांत करन (25) हादसे में जख्मी हो गया था। नेपाल से उसे किंग जार्ज चिकित्सा विविद्यालय (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेन्टर भेजा गया लेकिन निजी एम्बुलेंस चालक मरीज को गोमतीनगर स्थित जेनिस हॉस्पिटल ले आया। आरोप है कि फटी आंत के ऑपरेशन के नाम पर मरीज से छह दिन में करीब चार लाख पये वसूल लिए गये। मरीज की मां विनीता का आरोप है कि अस्पताल का दलाल राजू उसे बहकाकर निजी अस्पताल ले जाने का आरोप लगाया। स्वास्य विभाग ने महिला तीमारदार की शिकायत पर अस्पताल के दलाल राजू का नाम दर्ज कर लिया है। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. मनोज यादव ने बताया कि नेपाली मरीजों की खरीद–फरोख्त करने वाले अस्पताल–दलालों की सूची तैयार की जा रही है, इसमें दलालों को चिन्हित करके उन पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि नेपाल से आठ से दस मरीज उपचार के लिए रोजाना लखनऊ केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर, लोहिया संस्थान, पीजीआई आते हैं लेकिन एम्बुलेंस चालकों से सांठगांठ करके उन्हें सीधे निजी अस्पताल पहुंचाया जाता है।

प्याज के दामों में गिरावट शुरू

लखनऊ (संवाददाता)। प्याज की आवक बढ़ने से दामों में तेजी से गिरावट शुरू हो गयी है। को दुबग्गा थोक मंडी में प्याज 30 से 50 रुपये कि बिका है। इससा असर फुटकर बाजार पर भी दिखायी देने लगा है। फुटकर दुकानदारों पास भी प्याज 65 से 80 रुपये तक आ गया है। इसी तरह आलू तथा मटर की भी लोकल आवक बढ़ने से दामों में गिरावट हुई है। बीते तीन दिनों में प्याज की दरों में करीब दस रुपये की कमी आयी है। दो दिन पहले तक थोक मंडी में 60 से 65 रुपये किलो बिक रहा प्याज को 50 रुपये तक पहुंच गया है। इसका असर फुटकर मंडियों पर भी पड़ा है। चार दिन पहले तक फुटकर बाजार में प्याज 100 रुपये किलो तक पहुंच गया था। इसके साथ ही मटर के दाम 40 से 50 रुपये, आलू के दाम 30 से 35 रुपये तक पहुंच गये थे। प्याज कारोबारियों का कहना है कि लोकल में फतेहपुर तथा मध्य प्रदेश के खंडवा से नयी प्याज मंडियों में आने लगी है। कुछ ही दिनों में फतेहपुर के साथ ही कौशाम्बी, इटावा, झासी, बांदा जैसे जनपदों से लोकल प्याज की आवक शुरू हो जाएगी।

मंत्री से मिलकर की तबादलों में गड़बड़ी की शिकायत

लखनऊ (संवाददाता)। लिपिक संवर्ग के तबादले में गड़बड़ी समेत आठ सूत्री मांगों को लेकर यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आमरण अनशन को भी जारी रही। इस बीच आज पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्य मंत्री व प्रमुख सचिव स्वास्य से मिलकर उन्हें आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही निदेशक प्रशासन को मामला में गंभीरता दिखाने की निर्देश दिया है। साख बात यह रही कि प्रमुख सचिव चिकित्सा देवेश चतुव्रेदी से मुलाकात के बाद धरने पर बैठे प्रांतीय महामंत्री ग्रिजेश पाण्डेय की तबीयत अचानक खराब होने लगी । अधिकारी एक्टिव हुए और आमरण अनशन पर चल रहे यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री का तुरंत बलरामपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा जांच करायी गयी। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार और शासन के सम्पर्क में हैं और जल्द से जल्द मांग पूरी होनी चाहिए। धारने पर बैठे प्रांतीय महामंत्री ग्रिजेश पाण्डेय ने बताया कि घारा 144 लागू होने के कारण सिर्फ चार पदाधिकारी की धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के राजाज्ञा 24 मई 2019 का अनुपालन चिकित्सा स्वास्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। इसके कारण संगठन के आठ सूत्रीय मांग पत्र पर कोई भी अधिकारी वार्ता कर न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। मांगों के संबंध में उन्होंने बताया कि चिकित्सा स्वास्य प्रशासन द्वारा वार्षिक स्थानांतरण नीति के विरूद्ध किये गये स्थानांतरण को 15 सितम्बर तक निरस्त किया जाये। इसके अलावा प्रदेश के जिन जनपदों में उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के आदेश 29.9.2015 के अनुसार 30 सितम्बर 19 तक जनपदीय कार्यकारिणियों का गठन कर प्रांतीय संघ एवं निदेशक प्रशासन महोदया को सूचित किया जाए। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक धारना खत्म नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के उपाध्यक्ष एसपी सिंह, राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्र प्रताप सिंह, यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक महीपत राय वर्मा तथा यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद कुमार सैनी मौजूद थे।

प्रदर्शनी में दिखा बुनकरों का कौशल

लखनऊ (संवाददाता)। कैसरबाग सफेद बारादरी में हस्तशिल्पी सिल्क प्रदर्शनी 2019 का शुभारम्भ भाजपा विधायक सुरेश श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। सात जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न रेशम साड़ी बुनकर, हैंडलूम क्लस्टर और रेशम सहकारी समितियों के उत्पादों को खरीदा जा सकेगा। सफेद बारादरी में आयोजित इस प्रदर्शनी के आयोजक जावेद मकसूद, शहजान अब्बास नकवी ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सिल्क से बने उत्पादों को अपने ग्राहकों को बिना किसी कठिनाई के सुलभ तरीके से सीधे ग्राहकों को उपलब्ध कराना है। हस्तशिल्पी आयोजक नकवी ने यह भी बताया कि शादी व ईद को दृष्टिगत रखते हुये अरिनी सिल्क साड़ीज, क्रेप और जाज्रेट सिल्क साड़ीज, शिफान रेशम साड़ीज, तस्सार रेशम साड़ीज और सूट, कांजीवरम सिल्क साड़ी और वेडिंग साड़ीज, डिजाइनर फैंसी साड़ीज, दर्मावरम सिल्क साड़ीज, कच्चे रेशम और तस्सार, जूट सिल्क साड़ीज, ढाका सिल्क साड़ीज, हैंडलूम रेशम कॉटन साड़ीज, सिल्क ब्लेंड्स साड़ीज एंड स्टोल, सिल्क शल, उपपाडा, गडवाल, पैठानी साड़ी, मंगलागिरि और पोचंपल्ली सिल्क साड़ीज जैसे देशभर के विभिन्न उत्पाद इस एक्सपो में उपलब्ध होंगी।

भावनाशील को कॅरियर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता : निधि

लखनऊ (संवाददाता)। टीवीएफ के नये शो ''क्यूबिकल्स' से चर्चा में आयीं कलाकार निधि बिष्ट ने कहा कि यदि आपमें लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता है तो आपको कॅरियर में पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। कर्मचारियों एवं उनके मैनेजर्स के बीच प्यार–नफरत के संबंध पर आधारित टीवीएफ के इस शो में निधि मेघा अस्थाना का किरदार निभा रही हैं। शो में वह एक समझदार टीम लीडर हैं और जानती हैं कि अपना काम कैसे करवाया जाए। उनके जैसा सीनियर हर कोई चाहता है। कापरेरेट जिन्दगी के अपने व्यक्गित अनुभवों के बारे में निधि ने कहा कि सौभाग्य से क्रिएटिव क्षेत्र में आने से पहले उन्होंने कापरेरेट जिन्दगी में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं, वो अनेक विषयों पर अपने बस की आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाते। यदि आप भावनाशील हैं तो कॅरियर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगालखनऊ (संवाददाता)। किंग जार्ज चिकित्सा विविद्यालय (केजीएमयू) में रैन बसेरे में को आयोजित क्रिसमस–डे उत्सव में बच्चों को उपहार बांटे गये। ईर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में कैंसर पीड़ित बच्चों को ऊनी कैप, सॉक्स, बैलून और खाने–पीने की चीजें उपहार स्वरूप दी गयीं। इस मौके पर संस्था की संस्थापक सपना उपाध्याय, लायंस क्लब कैन्टोंमेन्ट, शेशू लवानिया, सपना गोयल, उमा भार्गव, सुमन पाहवा और डा. अरुना नारायन का सहयोग रहा।

सम्पादकीय
योजनाओं का असर

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अटल भूजल योजना की शुरुआत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और उपयोगी योजना की नींव रखी। छह हजार करोड़ रुपये वाली इस योजना का उद्देश्य भूजल स्तर को उठाना और जल संकट से निपटना है। यह योजना देश के उन सात राज्यों पर केंद्रित हैं जहां भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन यह ध्यान रहे कि ऐसा अन्य राज्यों में भी हो रहा है। यह वक्त की मांग है कि अन्य राज्य अपने स्तर पर भूमिगत जल के गिरते स्तर की चिंता करें। जल को संरक्षित करने का काम केवल केंद्र सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जल संरक्षण के मामले में मोदी सरकार ने अपनी गंभीरता का परिचय तभी दे दिया था जब दोबारा सत्ता में आने के बाद जल संसाधन और पेयजल मंत्रलय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रलय का गठन किया था। ऐसा करके उसने जल जीवन अभियान के तहत हर घर को नल से जल पहुंचाने की योजना पर भी काम शुरू किया। यह भी एक महत्वाकांक्षी योजना है। वास्तव में ऐसी योजनाओं के जरिये ही भावी जल संकट से निपटा जा सकता है। यह उम्मीद करनी चाहिए कि मोदी सरकार जल संबंधी जिन भी योजनाओं पर आगे बढ़ रही है उन्हें वैसी ही सफलता मिले जैसी विकास एवं जनकल्याण संबंधी अन्य योजनाओं को मिली है।

इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में शुरू की गईं रसोई गैस, आवास, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इन योजनाओं की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण मोदी सरकार की शानदार वापसी से मिलता है। अपनी विकास एवं जनकल्याण संबंधी योजनाओं के अमल में कहीं अधिक सक्षम होने के बाद भी मोदी सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है कि उसके राजनीतिक विरोधी जब–तब ऐसा माहौल तैयार करने में क्यों सफल हो जा रहे हैं कि इस सरकार को जनता के हितों की परवाह नहीं और वह तो अपनी किसी गुप्त एजेंडे पर काम कर रही है? इस सवाल पर विचार करने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि हाल में नागरिकता कानून पर सुनियोजित दुष्प्रचार के तहत एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया जैसे सरकार ने कोई जनविरोधी और संविधान विरोधी काम कर दिया है। मोदी सरकार और साथ ही भाजपा को इस पर ध्यान देना ही होगा कि झूठ का इतना बड़ा पहाड़ कैसे खड़ा हो गया? सरकारी तंत्र और साथ ही भाजपा के तमाम सांसद एवं विधायक समय रहते इस झूठ की काट क्यों नहीं कर सके? सरकार को चाहिए कि वह अपने प्रति जनता के भरोसे की डोर को और मजबूत करे।

भाजपा के सामने चुनौती और अवसर

झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा भाजपा के लिए चेतावनी, चुनौती और अवसर, तीनों लेकर आया है। मतदाताओं ने एक बार फिर साबित किया कि प्रधानमंत्री मोदी जब अपने लिए वोट मांगते हैं तो वह उनकी झोली भरने में संकोच नहीं करता, पर जब वे अपनी प्रदेश सरकार या प्रदेश इकाई के लिए वोट मांगने आते हैं तो उसका रवैया बदल जाता है। मतदाता मोदी और भाजपा को अलग–अलग देखता है।

मतदाता एक तरह से गौतम बुद्ध के कहे अनुसार करता है। वह कुपात्र पर दया करने में विश्वास नहीं करता। उसकी नजर में रघुवर दास कुपात्र साबित हुए। मतदाता काफी अर्से से भाजपा को चेतावनी दे रहा है कि राज्य नेतृत्व पर ध्यान दीजिए। मोदी–शाह की कमाई का पुण्य कुछ तो पार्टी को मिल जाएगा, पर राज्य इकाइयोंध मुख्यमंत्रियों का पाप उन्हीं के साथ रहेगा। दिल्ली, बिहार, राजस्थान और अब झारखंड में वही कहानी दोहराई गई। 'मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं' का नारा भले ही केवल राजस्थान में लगा हो, लेकिन सुनाई इन राज्यों में भी दे रहा था। 1977 से अब तक के भाजपा मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो रघुवर दास कई पैमाने पर खराब मुख्यमंत्री गिने जाएंगे। लगता है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन न करने का खामियाजा भुगतने के बाद भी पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा।प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से लगता है कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने अनुभवों के आधार पर पार्टी के तौर–तरीके में बदलाव लाना चाहते हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद वह चाहते थे कि उन्हें काम करने की पूरी आजादी मिले। उन्होंने यह आजादी हासिल भी की। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी–शाह ने जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया उस पर पूरा भरोसा किया। काम करने की पूरी छूट दी। यहां तक कि पार्टी के भीतर ही अपने विरोधियों को कमजोर करने की भी इजाजत दी, लेकिन जिन पर भरोसा किया वे उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर रहे। दो इंजन वाली सरकारों को इन्होंने ऐसा बना दिया जिसमें एक ही इंजन काम करता है। भाजपा की ज्यादातर राज्य सरकारों के पास उपलब्धि के नाम पर केंद्र सरकार की योजनाओं की कामयाबी ही है। बात इतने तक ही सीमित नहीं है। भाजपा के ज्यादातर सांसदों और विधायकों के मन में एक बात घर कर गई है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुनाव जिताने के लिए मोदी–शाह तो हैं ही। पार्टी के लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति को रोकना मोदी–शाह की सबसे बड़ी चुनौती है। यह चुनौती और बड़ी हो जाएगी जब अमित शाह अध्यक्ष पद छोड़ेंगे।

चुनाव में हार–जीत के शोर में सबसे अहम बात की शायद अनदेखी हो रही है। मोदी के प्रधानमंत्री और अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद से भाजपा के सफर पर ध्यान देना जरूरी है। महाराष्ट्र में भाजपा चौथे से पहले नंबर और हरियाणा में तीसरे से पहले नंबर की पार्टी बन गई। यह उस समय हुआ जब मोदी लहर के अलावा उसे ऐंटी इन्कंबेंसी का फायदा मिला। पांच साल बाद अपनी सरकार की ऐंटी इन्कंबेंसी के बावजूद दोनों राज्यों में वह पहले नंबर की पार्टी बनी रही। त्रिपुरा, जहां पार्टी का कोई नामलेवा नहीं था, वहां वह सत्ता में आ गई। उत्तर प्रदेश में जहां 17 साल से पार्टी तीसरे नंबर पर थी वहां वह प्रचंड बहुमत से सत्ता में है। कर्नाटक में मई 2018 में बहुमत से भले ही थोड़ा कम रह गई हो, पर पहले नंबर की पार्टी बनी। असम सहित पूवरेत्तर राज्यों में भाजपा हाशिये से राजनीतिक वर्चस्व वाली पार्टी बनी। इसी तरह बंगाल और ओडिशा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई।

पिछले दो साल में पांच राज्यों में भाजपा की सरकार जाने की बड़ी चर्चा है। ये राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अब झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड की हार भाजपा को जरूर खलेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता में रहने के बाद पार्टी बाहर हुई है। वहीं, मध्यप्रदेश में 15 साल की सत्ता के बाद भी वह सत्ता से ज्यादा दूर नहीं गई। राजस्थान हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन की परिपाटी का अभी तक निर्वाह कर रहा है। महाराष्ट्र में तो गजब ही हुआ। उसे भाजपा की चुनावी हार कहना ज्यादती होगी। इसके अलावा एक और बड़ा काम मोदी–शाह की जोड़ी कर रही है–प्रदेश में नए और ज्यादातर जगह युवा नेतृत्व को उभारने की। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फड़नवीस, सर्वानंद सोनोवाल, विप्लव देव, जयराम ठाकुर और प्रमोद सावंत जैसे युवा हैं तो मनोहर लाल खट्टर और त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे नए नेता, लेकिन दिल्ली और बिहार में नेतृत्व का अभाव पार्टी के लिए समस्या बना हुआ है। हाल–फिलहाल इस समस्या के हल के आसार भी नहीं दिख रहे। कहते हैं कि युद्ध जीतने के लिए कुछ लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं। चार राज्यों की हार कुछ ऐसी ही है। भाजपा जिस राज्य में भी सत्ता से बाहर हुई है, वहां कांग्रेस की तरह मटियामेट नहीं हुई है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि राष्ट्रीय विमर्श भाजपा के हाथ से नहीं निकला है, बल्कि उसकी पकड़ और मजबूत हुई है। पिछले छह महीने में तीन तलाक, जम्मू–कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या पर अनुकूल फैसले से भाजपा और मोदी–शाह की स्थिति मजबूत ही हुई है। अब नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्ष के प्रायोजित हिंसक विरोध ने भाजपा के पक्ष में जैसा ध्रुवीकरण किया है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। यह काम भाजपा और पूरा संघ परिवार मिलकर अगले 10–20 साल में भी नहीं कर पाते।नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और अब एनपीआर का विरोध करके विपक्ष को लग रहा है कि उसने सरकार को घेर लिया है और मोदी–शाह को कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया है। विपक्ष दलों का यह मुगालता उन्हें आने वाले समय में भारी पड़ने वाला है। विपक्ष का यह दांव नए भौगोलिक क्षेत्रों में भाजपा के विस्तार का आधार बनेगा। बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र और केरल भाजपा के राजनीतिकध्चुनावी विस्तार के नए राज्य बनने वाले हैं। इनमें 2021 में बंगाल पहली बार भाजपा को सत्ता में पहुंचा दे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बयान से लग रहा है कि इस माहौल में उन्हें अवसर नजर आ रहा है। खासतौर से झारखंड में हार के बाद। उन्हें लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें लेने के लिए अब भाजपा को दबाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले तीन राज्यों में हार के बाद उसने यही किया था। इस बार उन्हें झटका लग सकता है। 2019 में केंद्र सरकार दांव पर थी। पार्टी कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती थी। इस बार दांव पर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद है।

मॉनिटरिंग की दरकार

उत्तराखंड में पलायन का दंश डोल रहे गांवों के विकास के मद्देनजर धानवर्षा तो खूब हो रही है, लेकिन इसके सार्थक नतीजे नजर नहीं आ रहे। पिछले तीन वर्षो की तस्वीर तो यही बयां कर रही है। न सिर्फ केंद्र, बल्कि राज्य सरकार से भी गांवों को खूब पैसा जारी किया गया। 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2015–16 से अब तक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों को 1694.40 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायतों को करीब एक हजार करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। यानी तीन वर्ष की अवधि में लगभग 2700 करोड़ का बजट। बावजूद इसके गांवों की तस्वीर में खास फर्क नजर नहीं आ रहा। ये जरूर है कि गांवों तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग तो दिखते हैं, लेकिन वहां अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। साफ है कि सिस्टम के स्तर पर कहीं न कहीं खोट है। यदि ऐसा नहीं होता तो बीते तीन सालों में 2700 करोड़ के बजट से हुए कार्यो के बूते गांव अपनी चमक बिखेरते दिखते। असल में गांव के लिए बजट तो जारी हो रहा, लेकिन इसके सदुपयोग और समय पर उपयोग के मोर्चे पर सिस्टम की बेपरवाही भारी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि विकास कार्यो पर नजर रखने को तंत्र न हो। प्रदेश से लेकर जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तर तक मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, लेकिन मशीनरी अपने इस दायित्व की तरफ क्यों आंखें मूंदे है, ये समझ से परे है। गांव के विकास के लिए आए बजट का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, कार्य ठीक से हो रहे हैं या नहीं, इनकी गुणवत्ता कैसी है, ये सब देखना तो मशीनरी का ही दायित्व है। यदि कहीं खामियां है तो उसे दुरुस्त कराना भी उसकी जिम्मेदारी है। मॉनिटरिंग के मोर्चे पर सुस्ती के इस आलम का ही नतीजा है कि गांव के हालात बदल नहीं रहे। ऐसे में वहां से बेहतर भविष्य के दृष्टिगत लोगों का पलायन नहीं होगा तो और क्या होगा। खैर, अब बीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुध ले की तर्ज पर चलते हुए मशीनरी को ज्यादा सक्रिय करने की आवश्यकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार इस बिंदु पर गंभीरता से कदम उठाते हुए मशीनरी के पेच कसेगी, तब जाकर ही गांवों को सरसब्ज बनाने की मुहिम आकार ले पाएगी। साथ ही जनसामान्य को भी इसके लिए शिद्दत से आगे आना होगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता शिद्दत से महसूस की जा रही है।

जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने की तैयारी

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) देश के सभी स्थानीय निवासियों की एक सूची है। यहां स्थानीय स्तर का अर्थ गांव, कस्बा, जिला से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तैयार करना है। गौरतलब है कि सिटिजनशिप एक्ट 1955 को 2004 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए प्रावधान जोड़े गए। नागरिकता कानून में ये प्राविधान किया गया है कि केंद्र सरकार देश के हर नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। सरकार देश के हर नागरिक का रजिस्टर तैयार कर सकती है और इसके लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण भी गठित किया जा सकता है। इसी एक्ट के सेक्शन 14 के तहत किसी भी नागरिक के लिए एनपीआर में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रावधान भी किया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का विचार एक दशक पहले ही रखा गया था। लेकिन उस समय नागरिकों को सरकारी लाभों के हस्तांतरण के लिए सबसे उपयुक्त आधार योजना का इससे टकराव हो रहा था। गृह मंत्रलय ने तब आधार की बजाय राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के विचार को आगे बढ़ाया, क्योंकि यह एनपीआर में पंजीकृत प्रत्येक निवासी को जनगणना के माध्यम से एक परिवार से जोड़ता था। वर्ष 2011 की जनगणना के लिए वर्ष 2010 में एनपीआर हेतु जानकारी एकत्र की गई थी। इस डाटा को 2015 में घर–घर सर्वे करके अपडेट किया गया था। हालांकि मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में आधार को सरकारी लाभों के हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण माना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बजाय आधार कार्ड की संकल्पना को तेजी से बढ़ाया।

वर्ष 2020 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए 21 बिंदुओं के आधार पर डाटा एकत्रित किया जाएगा, जबकि वर्ष 2010 का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 15 बिंदुओं के आधार पर एकत्रित आंकड़ों के अनुसार तैयार किया गया था। एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान माता–पिता की जन्म–तिथि और जन्म–स्थान को एक बिंदु के रूप में शामिल किया जाएगा, यह बिंदु पहले तैयार किए गए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में शामिल नहीं था। वहीं इस नेशनल पापुलेशन रजिस्टर में अंतिम निवास स्थान, पासपोर्ट नंबर, आधार आइडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वोटर आइडी कार्ड और मोबाइल नंबर को भी अपडेट आंकड़ों के रूप में शामिल किया जाएगा। यहां एक अहम सवाल यह उठता है कि सरकार को नागरिकों के बारे में इतने सारे आंकड़े क्यों चाहिए? इस पर केंद्र सरकार का मानना है कि प्रत्येक देश में प्रासंगिक जनसांख्यिकीय विवरण के साथ अपने निवासियों के व्यापक पहचान का डाटाबेस होना चाहिए। यह सरकार को बेहतर नीतियां बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मदद करेगा।

इससे आयुष्मान, उज्ज्वला, सौभाग्य जैसी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान आसान होगी। सही लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचे, यह भी सुनिश्चित हो सकेगा। इसके अलावा यह विभिन्न प्लेटफॉर्मो पर निवासियों के डाटा को सुव्यवस्थित करेगा। जैसे विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में किसी व्यक्ति के जन्म की अलग–अलग तारीख होना आम समस्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से इस समस्या का समाधान होने की संभावना है। यही नहीं जनसंख्या रजिस्टर मतदाता सूचियों में दोहराव की समस्या को भी दूर करेगा। इसके लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में एकत्र किए गए डाटा को आधार कार्ड जारी करने और इनके दोहराव को रोकने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार एनपीआर के तहत पहचान पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह एक स्मार्ट कार्ड होगा, जिसमें आधार का भी जिक्र होगा।

हालांकि कई राज्यों ने इस संबंध में अपनी असहमति भी जताई है जिसे देखते हुए इसके उद्देश्यों को पूरा होने में संशय पैदा हो गया है। राज्य सरकारों के सहयोग के बिना एनपीआर पूरा करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल होगा। एनपीआर नियमों के तहत स्थानीय, अनुमंडल, जिला रजिस्ट्रार और अपील अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार को करनी है। केंद्र सरकार चाहे तो स्वतंत्र एजेंसी से जनसंख्या डाटा जमा करवा सकती है, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए भी राज्य सरकार के अधिकारियों की जरूरत होगी। कुल मिलाकर व्यावहारिक रूप से, स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार के सहयोग के बिना इस प्रक्रिया को पूरा करना आसान नहीं होगा।

विपक्षी दलों ने इसको लेकर दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि सरकार एनपीआर के जरिये गुप्त रूप से एनआरसी लागू करने की योजना बना रही है। इस संबंध में फैलाई जा रही भ्रांतियों के बीच केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एनपीआर अपडेट करने के दौरान व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही सही माना जाएगा, उसे कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का विचार ऐसे समय में चर्चा में आया है जब आधार तथा निजता के मुद्दे पर बहस जारी है और यह भारत के निवासियों की निजी जानकारी का एक बड़ा हिस्सा एकत्र करने पर आधारित है। कई विशेषज्ञों ने यह भी चिंता जाहिर की है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर लोगों का निजी डाटा भी एकत्रित करता है, जिससे आम जनता के निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। लेकिन पायलट परियोजना से पता चला है कि अधिकांश लोगों को ऐसी जानकारी को साझा करने में कोई समस्या नहीं है।

हालांकि सरकार का पक्ष है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की जानकारी निजी और गोपनीय है, अर्थात इसे तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा। लेकिन डाटा की इस विशाल मात्र के संरक्षण के लिए किसी व्यवस्था पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस चिंता को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

सीएए यानी संशोधित नागरिकता अधिनियम और एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर देशव्यापी विरोध के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक तरह से देश भर में छह माह से अधिक समय से रह रहे निवासियों का समग्र डाटाबेस होगा। इसके तहत एक अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक देशवासियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए देश भर में घर–घर जाकर गणना करने की तैयारी है।

!! शिक्षित महिला !! !! शिक्षित समाज !!

जय बजरंग महिला इण्टर कालेज

मुँगरा बादशाहपुर,जौनपुर (उ0प्र0)

प्रवेश प्रारम्भ

कक्षा 9–(सम्बन्धित सभी विषय)

कक्षा 11–(मानविकी 'कला एवं विज्ञान वर्ग')

नोट–1. हाईस्कूल परीक्षा का परिणाम शतप्रतिशत रहा।
2. छात्राओं को प्रशिक्षित महिला शिक्षको द्वारा शिक्षण की व्यवस्था।
3. प्रयोगिक विषयों के लिए सुव्यवस्थित प्रयोग शालाएं।
4. छात्राओं के लिए कम्प्यूटर शिक्षा व्यवस्था।
5. छात्राओं के लिए स्वच्छन्द वातावरण।

मोबाइल नं0–9451117446

!! My Child !! !! My Future !!

जे0 बी0 पब्लिक स्कूल

नईबाजार, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर

प्रवेश प्रारम्भ

कक्षा 1 से 8 तक

नोट–1. बच्चों के लिए व्यवस्थित क्लास रूम।
2. अच्छी शिक्षा के लिए योग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन।
3. स्तरीय शिक्षा के लिए एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकों द्वारा अध्यापन।
4. बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं प्रयोग शाला।

मोबाइल नं0–9451117446

सर्दी में अधिकारियों को पसीना ला रहे विज

आजकल सूर्यदेव को भले ही कोहरे का बाउंसर फॉर्म में नहीं आने दे रहा है, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पूरी तरह फार्म में हैं। वह धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। पुलिस विभाग के अधिकारी सांसत में हैं। जो स्लिप में हैं वे भी और जो लॉन्ग ऑफ पर हैं वे भी। विज न जाने किस तरफ से गेंद बाउंड्री पार करा दें। और फिर फील्डर को मैदान से बाहर जाने या ट्रांसफर कर देने का फरमान जारी कर दें। यह विज का स्टाइल है। सो इस कड़कती ठंड में विज की कड़कती आवाज पुलिस अधिकारियों को सर्दी में भी गर्मी का एहसास कराते हुए पसीना–पसीना कर रही है। हालांकि इसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। दरअसल पिछले 23 वर्षो से मुख्यमंत्री खुद अपने पास गृह विभाग रखते थे। अब मुख्यमंत्री के पास कहां इतनी फुर्सत कि वह पुलिस पर ध्यान दें। विज की सीन में एंट्री क्या हुई, लगा गब्बर आ गया। वैसे विज का प्रचलित नाम गब्बर ही है। हरियाणा में किसी से पूछ लीजिए, गब्बर कौन है? वह छूटते ही बोलेगा– अनिल विज।

देखा–देखी पुण्य, देखा–देखी पाप रू एक दिन मनोहर स्वभाव वाले मुख्यमंत्री भी विज के रूप में प्रकट हो गए। सीधे करनाल तहसील कार्यालय पहुंचे। जब तहसील कार्यालयों में लिया राम– दिया राम की परंपरा पहले से चली आ रही है तो करनाल का तहसील कार्यालय इसके अनुपालन में पीछे क्यों रहता? लेकिन इस परंपरा को देख मनोहर, लाल हो गए। तहसीलदार–नायब तहसीलदार सहित चार को निलंबित कर दिया। लोगों को लगा कि वह सीनियर गब्बर बनने जा रहे हैं क्या? हालांकि अब तक उन्होंने फिर वैसा कोई शॉट नहीं खेला है। इससे अधिकारी राहत महसूस कर सकते हैं। लेकिन कब जाने अपने वरिष्ठतम कनिष्ठ का प्रदर्शन देख उनका मन फिर से जोरदार बैटिंग के लिए मचल जाए। अब उनका मन फिर मचले न मचले। उनके खेल मंत्री संदीप सिंह पिच पर उतरते ही विज की तरह आक्रामक मोड में आ गए थे और चर्चा में हैं। उनके विभाग वाले उन्हें सेकेंड गब्बर मानने लगे हैं।तड़पाए–तरसाए रे दिल्ली की कुर्सी रू सर्दी तो तड़पा–तरसा रही ही है, हरियाणा के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं को भी तड़पा–तरसा रही है। खास तौर से तीन प्रमुख नेताओं को। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा राज्यसभा की सदस्य हैं। वे चाहती हैं कि राज्यसभा में उनकी कुर्सी बरकरार रहे तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से चुनाव हार चुके अपने पुत्र पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद वह माननीय रहे नहीं। अब हुड्डा अगर अपने पुत्र को माननीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? हर पिता अपने पुत्र की राह के कांटे हटाता है।

विधायकों को सलाहकार बनाने पर राज्यपाल ने अमरिंदर से पूछा, वेतन–भत्ता क्या होगा

चंडीगढ़ । पंजाब में छह विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त करने के लिए पारित विधेयक राजभवन की आंखों में खटक रहा है। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने इस पर कई सवाल खड़े करके कैप्टन सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर कैप्टन सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर (प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) संशोधन विधेयक–2019 पास करवा लिया। इसमें विधायकों को लाभ के पद से बाहर कर दिया गया। पहले इसके लिए अध्यादेश लाया गया था। इसमें कुशलदीप सिंह ढिल्लों, कुलजीत नागरा, तरसेम सिंह डीसी, इंद्रबीर सिंह बुलारिया, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग व संगत सिंह गिलजियां को मुख्यमंत्री के सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। इसी मामले पर राज्यपाल ने सरकार से 13 सवाल पूछे हैं। कैप्टन बोले, विधेयक वापस नहीं किया, स्पष्टीकरण मांगा हैरू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस दावे को खारिज किया है, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल ने विधेयक वापस कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने केवल कुछ चीजों पर स्पष्टीकरण मांगा है और जल्द ही यह राज्यपाल को भेज दिया जाएगा। सिंह ने कहा कि संबंधित विभाग और अधिकारियों को राज्यपाल की ओर से पूछे गए सवालों का जल्द से जल्द जवाब भेजने को कहा गया है। सरकार ने छह में से पांच विधायकों कुशलदीप ढिल्लों, संगत सिंह गिलजियां, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, कुलजीत नागरा और इंद्रबीर सिंह बुलारिया को कैबिनेट रैंक व तरसेम सिंह डीसी को राज्यमंत्री का दर्जा दिया है।

उत्तर प्रदेश को जलाने वाले खुद से पूछें सवाल : मोदी

लखनऊ संवाददाता। मौका तो यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण और उनकी स्मृति में बनाए जा रहे चिकित्सा विश्वविद्यालय के शिलान्यास का था, लेकिन इन कार्यक्रमों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उप्र को हिंसा और आगजनी में झोंकने वालों को नागरिकता के दायित्वबोध का अहसास भी कराया। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदेश में हिंसा, आगजनी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से कहा किया कि वे अपने घरों में बैठकर खुद से सवाल करें कि क्या उनका रास्ता सही था? क्या उनकी प्रवृत्ति सही थी? जिन सरकारी संपत्तियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, क्या वे उनके बच्चों के काम आने वाली नहीं थीं? हिंसा में जो लोग मारे गए और पुलिसकर्मी घायल हुए, उनके परिजन के बारे में भी सोचें। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूबे में सत्ता के शीर्ष अधिष्ठान लोकभवन के परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। फिर उन्होंने राजधानी के चक गंजरिया में बनाए जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का लोकभवन सभागार में बटन दबाकर शिलान्यास किया। इसके बाद तकरीबन 35 मिनट के संबोधन में मोदी ने कहा कि आजादी के बाद हमने सबसे ज्यादा जोर अधिकारों पर दिया, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों, दायित्वों पर भी उतना ही बल देना है। हक के साथ दायित्व को भी याद रखना होगा। झूठी अफवाहों पर हिंसा करने और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों से उन्होंने आग्रह किया, 'यदि बेहतर सड़क, परिवहन व्यवस्था और सीवर लाइन उनका हक है, तो इन्हें सुरक्षित रखना भी उनका दायित्व है। यदि उत्तम व सुलभ शिक्षा हमारा हक है तो शिक्षण संस्थानों को सुरक्षित रखना और शिक्षकों का सम्मान हमारा दायित्व है। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पाना हमारा अधिकार है तो अस्पतालों की सुरक्षा और डॉक्टरों का सम्मान हमारा कर्तव्य है। सुरक्षित माहौल हमारा हक है तो उसे उपलब्ध कराने वाले पुलिस तंत्र का सम्मान भी हमारा दायित्व है।' मोदी ने कहा कि हक की सीमा है लेकिन कर्तव्य की भावना बहुत व्यापक है। यह भावना नागरिकों के साथ सरकारी तंत्र में भी होनी चाहिए। चुनौतियों को चुनौती देने का कोई मौका नहीं छोड़ा रू मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कसौटियों पर खरा ठहराया। उन्होंने कहा कि अटलजी कहते थे कि हर पीढ़ी को भारत की प्रगति का मूल्यांकन दो मानदंडों पर करना चाहिए। पहला, विरासत में मिलीं कितनी समस्याओं को हमने सुलझाया है। दूसरा, राष्ट्र के भावी विकास के लिए हमने अपने प्रयासों से कितनी मजबूत नींव रखी है। मोदी ने कहा कि हमने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को दूर किया है। अनुच्छेद 370 कितनी पुरानी बीमारी थी? कितनी कठिन लगती थी? हमें विरासत में मिली थी। हमने ऐसी कठिन चुनौती को सुलझाया। यह हुआ और आराम से हुआ। सबकी धारणाएं चूर–चूर हो गईं। अयोध्या विवाद के इतने पुराने मामले का शांतिपूर्ण समाधान कराया।

नागरिकता संशोधन कानून का नाम लिए बगैर कहा कि देश के विभाजन के बाद लाखों गरीब, जिनमें ज्यादातर दलित, वंचित और शोषित थे, अपना धर्म और बहू–बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान छोड़ भारत की शरण लेने को मजबूर हैं, उन्हें नागरिकता की गरिमा दिलाने का काम देश की 130 करोड़ जनता ने किया है। भारत यह आत्मविश्वास लेकर 2020 में प्रवेश कर रहा है। अब भी जो बाकी है, उनके समाधान के लिए हर भारतवासी पूरे सामर्थ्य से प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा, 'हम चुनौतियों को चुनौती देने का स्वभाव लेकर निकले हैं। हमने चुनौतियों को चुनौती देने का कोई मौका नहीं छोड़ा।' ये भी थे मौजूद रू कार्यक्रम में उप्र की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉ. दिनेश शर्मा सहित राज्य सरकार के मंत्री व भाजपा पदाधिकारी शामिल थे।

95वें जन्मदिन पर पूर्व पीएम वाजपेयी को राष्ट्रपति, पीएम ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली,। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 95वें जन्मदिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

वाजपेयी के स्मारक 'सदैव अटल' पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा स्वर्गीय वाजपेयी के परिजन मौजूद थे। 'सदैव अटल' को पिछले साल ही राष्ट्र को समर्पित किया गया है। वाजपेयी का जन्म वर्ष 1924 में ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में हुआ था और उनकी मृत्यु एम्स, नई दिल्ली में 16 अगस्त, 2018 को हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'देशवासियों के दिलों में बसने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मदिन पर नमन।' उन्होंने देश के विकास में दिवंगत वाजपेयी के योगदान से संबंधित एक वीडियो भी साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मदन मोहन मालवीय को भी उनके 158वें जन्मदिन पर नमन किया। उन्होंने लिखा, 'महामना पंडित मदनमोहन मालवीय को उनके जन्मदिन पर विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया।'केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, 'एक तरफ जहां उन्होंने कुशल संगठनकर्ता के रूप में पार्टी का अखिल भारतीय स्तर पर प्रसार किया तो दूसरी तरफ देश का नेतृत्व भी किया।' शाह ने कहा कि वाजपेयी सरकार में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में मिली जीत ने दुनिया भर में भारत की सशक्त छवि प्रस्तुत की। उन्होंने महामना मदनमोहन मालवीय को भी श्रद्धांजलि दी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 'स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी आजाद भारत के उन राजनीतिज्ञों में शामिल हैं, जिन्होंने राजनीति और कूटनीति को नया आयाम व नई दिशा दी। जन्मदिन पर उन्हें नमन।'

भाजपा की ओर से देश के विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान नेताओं ने अपने प्रिय नेता को याद किया। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस दौरान वाजपेयी से जुड़ी अपनी यादों को ताजा किया। कई नेता वाजपेयी को याद कर भावुक हो गए।

उपभोक्ता परिषद ने तय किया नए साल का एजेण्डा

लखनऊ (संवाददाता)। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर को फील्ड हास्टल स्थित कार्यालय एक बैठक की गयी। बैठक में उपभोक्ता परिषद ने पूरे वर्ष 2019 में ''क्या खोया, क्या पाया' की समीक्षा की गयी और यह तय किया की आने वाले नये वर्ष 2020 में किन मुद्दों पर संघर्ष और उपभोक्ता हित की लड़ाई को तेज किया जाएगा जिससे उपभोक्ताओ को मिलने वाले उनके अधिकार सुरक्षित रहें। बैठक में कहा गया कि अब जो वर्ष जा रहा उसमें उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ताओं के हित में बहुत कामयाबी हासिल की चाहे वह रेगुलेटरी सरचार्ज को खत्म कराने का मामला रहा हो सिस्टम लोडिंग को खत्म कराने का मामला रहा है मुआवजा कानून बनवाने का मामला रहा हो या फिर बीपीएल की दरों में बढ़ोतरी न होने देने का मामला रहा हो या फिर उपभोक्ता हित में अनेको कानून बनवाने का मामला हो बिल्डरों के सिंगल प्वाइंट कनेक्शन खत्म कराने का मामला हो सभी पर जीत हासिल हुई जिसमे विद्युत नियामक आयोग की उपभोक्ता हित में निर्णय करने की अहम् भूमिका रही ।वही उपभोक्ता परिषद की लड़ाई को उपभोक्ता हित में सफल बनाने में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का अहम् योगदान रहा जिन्होने हमेसा उपभोक्तओ का पूरा साथ दिया।उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा न कहा उपभोक्ता परिषद् की सबसे बड़ी चुनोती नये साल वर्ष 2020 में यह होगी कि विजली कम्पनियों के ऊ पर वर्ष 2019 के टैरिफ आदेश में उपभोक्ता परिषद की लम्बी लड़ाई के बाद जो कुल उदय व ट्रूप में रुपया 13337 करोड़ का लाभ निकला है उसका लाभ उपभोक्तओ को दिलाया जाय और दूसरा सबसे बड़ा मुदा विगत दिनों जारी मुआवजा कानून जिस पर बहुत जल्द अधिसूचना जारी होना है ।

उसे पूरे प्रदेश में सफलता पूर्वक लागु कराया जाना एक कठिन लक्ष है। बिजली दरों में कमी कराने का विचाराधीन मुदा भी काफी अहम् है। उपभोक्ता परिषद नये साल में उपभोक्तओ को अनेको ऐसे तोहफे दिलाने में कामयाब होगा जो वर्तमान में पाइप लाइन में नियामक आयोग में विचाराधीन है । उपभोक्ता परिषद ने अपने कायरे कि कि समीक्षा और नये वर्ष 2020 में उपभोक्ता हित के विचाराधीन मुद्दों पर अपना संघर्ष का एजेण्डा तय कर दिया है अब उसी पर संघर्ष तेज किया जाएगा नये साल में उपभोक्तओ को उपभोक्ता परिषद दिलाएगा अनेको बड़ा तोहफा जो वर्तमान में बिचारधीन है।

मुंबई में उप्र मूल के लोगों के गांव–घरों की समस्याओं का होगा निपटारा

मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई में रहने वाले प्रदेश के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग मानते हुए यहां एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। उपनिदेशक स्तर का यह अधिकारी उत्तर प्रदेश मूल के मुंबई में रह रहे लोगों की उनके गांव–घर संबंधी समस्याओं के निराकरण में उनकी मदद करेगा। दो माह पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार करने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने का वादा किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह सुझाव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके राम नाईक ने दिया था। वैसे मुंबई भाजपा के महासचिव अमरजीत मिश्र एवं महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश मूल के लोगों के बीच काम कर रहे संगठन उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम (यूपीडीएफ) की ओर से भी यह मांग लंबे समय से उठाई जाती रही थी। राम नाईक का सुझाव था कि यह अधिकारी सचिव स्तर का होना चाहिए, जो सिर्फ सिफारिश नहीं, बल्कि संबंधित विभागों को निर्देश भी दे सके।

पूर्व प्रधान हत्याकाण्ड : जांच के लिए बनी तीन टीमें

लखनऊ (संवाददाता)। पारा क्षेत्र में रविवार रात सलेमपुर पतौरा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान व बसपा नेता की निर्मम हत्या मामले में पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले के खुलासे के लिए तीन टीमें बनाई गयी हैं। पुलिस उस व्यक्ति को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसके साथ हत्या से पूर्व सन्तराम के घर में साथ–साथ खाना खाया था। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले की जांच कर रहे एएसपी नगर (पूर्वी) सुरेश चन्द्र रावत का कहना है कि पुलिस ने रामकुमार के भाई रमेश कुमार बबली से भी पूछताछ की है। उसने अपनी तहरीर में अभी तक किसी को नामजद नहीं किया है। इसके अलावा जमीन विवाद की भी जांच कर रही है, जिस विवादित जमीन पर रामकुमार का शव दफनाया गया है। मृतक की मां विशुन देई मौजूदा प्रधान हैं। बताया जा रहा है कि मोहान रोड स्थित खसरा संख्या 660 पर गांव के ही रामकरन और मुन्ना से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि उक्त खसरा नम्बर पर सिविल जज दीवानी में मुकदमा विचाराधीन है, जिसपर परमानेन्ट स्टे चल रहा है। वहीं प्रधान के परिजनों का कहना है कि उक्त खसरा नम्बर में करीब दो बीघा जमीन ग्राम पंचायत की है। वहीं मौके पर मौजूद राजस्व टीम के कानूनगो करूणा शंकर का कहना है कि इस खसरा संख्या में कोई ग्राम पंचायत की जमीन होने की अभी तक पुष्टी नहीं हुई है, जिसे राजस्व अभिलेखों में देखी जाएगी। बताते चले कि पारा के सलेमपुर पतौरा ग्राम पंचायत में रविवार रात करीब 8.30 बजे मित्र सजीवन लाल गौतम के घर जन्मदिन समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे पूर्व प्रधान राजकुमार गौतम उर्फ गुड्डू की गांव में ही बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीच गांव में इस सनसनीखेज हत्याकाण्ड के बाद नाराज ग्रामीणों ने देर रात तक एसएसपी को मौके पर ही बुलाने की बात पर अड़े रहे और जमकर हंगामा करते रहे थे। बाद में मौके पर पहुंचे एएसपी सुरेश चन्द्र रावत ने मामला शान्त कराया था और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज था।

जाली आईडी बना मरीज व तीमारदारों से की वसूली

लखनऊ (संवाददाता)। केजीएमयू में गरीबों व बेसहारा मरीजों की निशुल्क सेवा करने वाली युवती के पिता ने चौक कोतवाली में एक युवक के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप है कि आरोपित ने धोखे से बेटी की आईडी की फोटो हासिल कर जाली आईडी बनवायी और फिर वसूली की। इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।चौक के नक्खास स्थित बिल्लौचपुरा मोहल्ला में हुमांयू परिवार के साथ रहते हैं। उनकी बेटी लेवी करीब सात साल से अपनी बहन ईसा की मौत के बाद उसकी याद में केजीएमयू में गरीब, बेबस, बेसहारा मरीजों की निशुल्क व बिना किसी स्वार्थ के सेवा करती है। इस बात की जानकारी केजीएमयू के अधिकारी व कर्मचारी के पास है।आरोप है कि करीब तीन माह पहले सआदतगंज के कटरा निवासी मो. सादिल ने जाल में फंसाकर बेटी लेवी की केजीएमयू की आईडी लेकर फोटो खींच ली। उसके बाद वैसे ही अपने नाम से आईडी बनाकर केजीएमयू में मरीजों व तीमारदारों को बहलाकर वसूली करने लगा। जानकारी होने पर जब उसे टोका गया तो उसने खुद को पत्रकार बताया। धोखाधड़ी की शिकायत पीड़ित हुमांयू ने चौक कोतवाली में सोमवार को दर्ज करायी है।

जाली आईडी बना मरीज व तीमारदारों से की वसूली

लखनऊ (संवाददाता)। केजीएमयू में गरीबों व बेसहारा मरीजों की निशुल्क सेवा करने वाली युवती के पिता ने चौक कोतवाली में एक युवक के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप है कि आरोपित ने धोखे से बेटी की आईडी की फोटो हासिल कर जाली आईडी बनवायी और फिर वसूली की। इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।चौक के नक्खास स्थित बिल्लौचपुरा मोहल्ला में हुमांयू परिवार के साथ रहते हैं। उनकी बेटी लेवी करीब सात साल से अपनी बहन ईसा की मौत के बाद उसकी याद में केजीएमयू में गरीब, बेबस, बेसहारा मरीजों की निशुल्क व बिना किसी स्वार्थ के सेवा करती है। इस बात की जानकारी केजीएमयू के अधिकारी व कर्मचारी के पास है।आरोप है कि करीब तीन माह पहले सआदतगंज के कटरा निवासी मो. सादिल ने जाल में फंसाकर बेटी लेवी की केजीएमयू की आईडी लेकर फोटो खींच ली। उसके बाद वैसे ही अपने नाम से आईडी बनाकर केजीएमयू में मरीजों व तीमारदारों को बहलाकर वसूली करने लगा। जानकारी होने पर जब उसे टोका गया तो उसने खुद को पत्रकार बताया। धोखाधड़ी की शिकायत पीड़ित हुमांयू ने चौक कोतवाली में सोमवार को दर्ज करायी है।

क्लोन बना युवक के खाते से उड़ाए 1 लाख

लखनऊ (संवाददाता)। गोमतीनगर के विनयखण्ड–5 में नीरेन्द्र कटियार रहते हैं। उनका बचत खाता बैंक ऑफ बड़ोदा बैंक में है। उनका कहना है कि जालसाज ने क्रेडिट कार्ड का क्लोन बनाकर पेटीएम व मोबीक्विक के द्वारा खाते से बीते 9 अगस्त व 9 सितम्बर को 1 लाख रुपये उड़ा लिए। थाने पर सुनवायी न होने पर पीड़ित ने पोर्टल पर शिकायत की। जिसके बाद गोमतीनगर पुलिस ने सोमवार को धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

लखनऊ (संवाददाता)। गोमतीनगर के विनयखण्ड–5 में नीरेन्द्र कटियार रहते हैं। उनका बचत खाता बैंक ऑफ बड़ोदा बैंक में है। उनका कहना है कि जालसाज ने क्रेडिट कार्ड का क्लोन बनाकर पेटीएम व मोबीक्विक के द्वारा खाते से बीते 9 अगस्त व 9 सितम्बर को 1 लाख रुपये उड़ा लिए। थाने पर सुनवायी न होने पर पीड़ित ने पोर्टल पर शिकायत की। जिसके बाद गोमतीनगर पुलिस ने सोमवार को धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

अटल स्वास्थ्य मेले में 4,293 मरीजों की जांच

लखनऊ (संवाददाता)। चौक स्थित कालीचरण डिग्री कालेज में मंगलवार को दो दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का समापन हो गया, इसमें 4,293 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गयी। इसके साथ ही 93 लोगों का अल्ट्रासाउंड तथा 65 का एक्स –रे किया गया। दो दिन में छह हजार से अधिक मरीजों को उपचार मिला। मेला के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमन्त्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि हम सभी को स्वस्थ रहना जरूरी है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना समेत कई अन्य योजनाएं शुरू की हैं। जिनके माध्यम से लोग अपना निरूशुल्क इलाज करा सकते हैं। प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अटल जी की जयंती पर इससे बेहतरीन आयोजन नहीं हो सकता है। अब हर वर्ष अटल जी की जयंती पर इस तरह के स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जायेगा। यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अटल जी का लखनऊ से पुराना रिश्ता रहा है। इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन कर उनको हम सभी ने याद किया है। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने कहा कि इस मेले के माध्यम से लोगों को निरूशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि वह भी अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह के मेले का आयोजन कराएंगे। विधायक पंकज सिंह ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराने की दिशा में यह मेला बड़ी भूमिका निभाएगा। भाजयुमो नेता नीरज सिंह ने कहा कि इस स्वास्थ्य मेले से हमने समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया है। वहीं मुख्य चिकित्साधिकारी डा. नरेंद्र अग्रवाल ने स्वास्थ्य मेले समापन पर लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महिला स्वास्थ, बाल स्वास्थ व परिवार नियोजन विषय पर वाराणसी के मंचदूतम नाट्य समूह द्वारा सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफार) के सहयोग से खुशियां आंचल में नुक्कड़ नाटक के मंचन से लोगों को जागक किया गया। नारायण सेवा संस्थान द्वारा 10 दिव्यांगों को व्हील चेयर, 15 को ट्राइसाइकिल और 65 को कृत्रिम अंग दिए गए। कुछ मरीजों को उदयपुर स्थित केंद्र रेफर किया गया। इसके साथ ही एल्म्स द्वारा हेयरिंग एड का भी वितरण किया गया। इसके साथ ही भारतीय डाक विभाग द्वारा बचत सम्बंधी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। उज्ज्वल सेवा संस्थान द्वारा कपड़ों का वितरण किया गया। अंत में प्रतिभागी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक डा. नीरज बोरा, सुरेश श्रीवास्तव, सुरेश तिवारी, भाजपा के नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव राघवेन्द्र, एकेटीयू के कुलपति डा. विनय पाठक, डिप्टी सीएमओ डा. एमके सिंह, डा. डीके बाजपेयी, जिला स्वास्थ शिक्षा एवं सूचना अधिकारी योगेश रघुवंशी और स्वास्थ विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। स्वास्थ मेले में केजीएमयू, पीजीआई, सहारा हास्पिटल, अपोलो अस्पताल, मिडलैंड हॉस्पिटल, कैरियर इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल आदि संस्थानों के सहयोग से हुआ।

13 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

लखनऊ (संवाददाता)। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी (45) की हत्या में शामिल 13 आरोपितों के खिलाफ एसआईटी ने मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दिया। सीजेएम मीरा गोठलवाल ने चार्जशीट मंजूर करते हुए 4 जनवरी की तारीख दी है।नाका के खुश्रेदबाग कालोनी स्थित हिंदू समाज पार्टी के कार्यालय में बीते 18 अक्टूबर को भगवा कपड़े पहने बदमाशों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी (45) की नृशंस हत्या कर दी थी। कातिल हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर कार्यालय आए थे। बातचीत के दौरान बदमाशों ने डिब्बे से रिवाल्वर व चाकू निकालकर कमलेश पर हमला कर हत्या की थी। मामले में पत्नी किरन तिवारी ने नाका कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पूरे मामले की जांच आईजी रेंज एसके भगत की अगुवायी में बनी एसआईटी कर रही थी। हत्याकाण्ड के 74 दिन बाद मंगलवार को एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। 13 आरोपितों में अशफाक हुसैन, मोइनुद्दीन, पठान रशीद, फैजान मेम्बर, मोहसिन सलीम शेख, सैयद आसिफ अली, कैफी अली, मोहम्मद नावेद, रईस अहमद, मो. आसिफ रजा, मो. कामरान अशरफ, युसूफ खान व मो. जाफर को आरोपित बनाया है।सभी आरोपितों के खिलाफ एसआईटी ने हत्या (302 आईपीसी), आपराधिक साजिश रचने (120–बी), साक्ष्य छिपाने (201 आईपीसी), हत्यारोपितों को संरक्षण देने, जाली दस्तावेज बनाने, धोखाधड़ी (420 आईपीसी), आर्म्स एक्ट व आईटी एक्ट में आरोप तय किये हैं। चार्जशीट मंजूर करते हुए सीजेएम मीरा गोठलवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर जेल में बंद आरोपितों की सुनवायी करने के साथ ही मामले में 4 जनवरी को अगली सुनवायी की तारीख तय की है।बताया जा रहा है कि बरेली के कोहाडापीर से पकड़े गये मौलाना कैफी अली पर हत्यारों की मदद का आरोप है।

चालकों के लिए आयोजित हुआ प्रशिक्षण शिविर

लखनऊ (संवाददाता)। खण्डग्रास सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को होगा। अमावस्या तिथि मूल नक्षत्र और धनु राशि में लगेगा। यह ग्रहण वलयाकार कंकड़ाकृति चांदी के कंगन के आकार का सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण का स्पर्श प्रातरू 8रू20 से चरम अवस्था में प्रातरू 9रू37 और मोक्ष प्रातरू 11रू07 तक होगा। ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व 25 दिसम्बर को सायंकाल 8 से आरम्भ होगा। सूतक के चलते मंदिर के द्वार बुधवार रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। स्वास्तिक ज्योतिष केन्द्र के ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि सूतक काल में भोजन आदि करना माना है लेकिन वृद्धों, बच्चों एवं रोगियों पर लागू नहीं होता है। ग्रहण काल में मन्दिर में प्रवेश और मूर्तियों का स्पर्श भी मना है लेकिन जप एवं मंत्र सिद्धि आदि फलदायी है। सूर्य ग्रहण में सूर्य के मंत्र या महामुत्युंजय मंत्र का जाप किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत के अलावा यह सूर्य ग्रहण सऊदी अरब, कतर, सुमात्रा, मलेशिया, ओमान, सिंगापुर, नॉर्थन मरिना आईलैंड, श्रीलंका और बोर्नियो में दिखेगा। सूर्य ग्रहण में 30 दिन के अन्दर ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव पड़ते है। ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और ग्रहण के कारण पृवी पर कास्मिक ऊर्जा का ह्रास होता है, जिससे पृवी पर प्राकृतिक आपदायें आती है। सूर्य ग्रहण के समय 6 ग्रहों (सूर्य, चन्द्रमा, बुध, गुरु, शनि एवं केतु) की युति है। ऐसे में सत्ता वर्ग के लिए परेशानी दायक प्राकृतिक आपदाय एवं जन धन हानि की आशंका भी व्यक्त करती है। कर्क, तुला, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए शुभ फलदायक मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक राशि वालों के लिए मिश्रित तथा वृष कन्या धनु मकर राशि वालों के लिए सामान्य फलदायक होगा। ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है ग्रहण में सोना भोजन करना मूर्ति स्पर्श करना आदि वर्जित है गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में सावधानी रखें ग्रहण देखना भी सही नहीं होता है। इस समय चाकू, कैंची, सुई का प्रयोग न करें। इन्हें पेट पर गेरू का लेप करना चाहिए। अपने साथ नारियल भी रखना चाहिए। इस समय यात्रा करना सही नहीं खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते या कुशा डालना चाहिए। सूतक काल समाप्त होने के बाद पीने के पानी को अवश्य बदलें।

जामिया हिंसा को सफल देख, पीएफआई ने लखनऊ को किया था टारगेट

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में होने वाले प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने के लिए पापुलर फ्रंट ऑफ इण्डिया ने दूसरे राज्यों के लोगों को बुलाया था। पुलिस अफसरों का मानना है कि जामिया में हुए हिंसक प्रदर्शन के ठीक बाद लखनऊ में भी इसी तरह से धरना कर उसकी आड़ में हिंसा फैलाने की पटकथा तैयार कर ली गयी थी। पीएफआई ने दूसरे राज्यों के अलावा कश्मीर में भी सेना पर पत्थर चलाने में माहिर लोगों को लखनऊ में बुलाया था।बीते गुरुवार को हजरतगंज के परिवर्तन चौक, हसनगंज के मदेयगंज व ठाकुरगंज के सतखण्डा में हुई हिंसा के मामले में पुलिस दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया था।

इनमें गिरफ्तार किये गये सागर अली, संजू अली, शाह आलम, असलम, सलेदुल व खेरुल समेत अन्य पश्चिम बंगाल के माल्दा से आए थे। इसके साथ ही आसाम के रहने वाले लोग भी गिरफ्तार हुए थे।ये लोग बीते कई दिन पहले ही राजधानी में आमद कर चुके थे। कुछ छात्रावासों में रूके थे तो कुछ होटल, धर्मशाला व मुसाफिरखाने में शरण लिए थे। '

प्रभु यीशु को यादकर मना क्रिसमस–डे

जौनपुर । प्रभु यीशु के जन्मोत्सव क्रिसमस–डे को यादगार बनाने के लिए पचहटिया स्थित सेंट पैट्रिक स्कूल में बने चर्च को शानदार तरीके से सजाने के साथ ही प्रभु यीशु को याद किया गया। बेतुलहम के जंगल के दृश्य चुन–चुन कर सजाए गये। एक तरफ राजा हीरोद का महल सजा तो, दूसरी ओर वह गोशाला, जिसमें मां मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया।

चर्च में मसीही समुदाय के बीच फादर पी विक्टर व फादर जोसेफ ने सुबह साढ़े नौ बजे पारंपरिक परिधान में पहुंचकर पूजा की। इसी के साथ ही प्रभु यीशु को याद किया गया। इस दौरान पवित्र बाइबिल के तीन पाठ हुए। मंगलवार की रात 12 बजे के बाद सजी गोशाला की झांकी में प्रभु यीशु के बाल रूप के दर्शन करने वालों की भीड़ लग गई। बुधवार की सुबह नौ बजे भी प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें मसीही समाज के अन्य अनुयायी भी पहुंचे। प्रधानाचार्य सिस्टर जेसी, सिस्टर प्रीति, रीटा, अन्नु सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। शाहगंज स्थित सेंट थामस इंटर कालेज के चर्च में फादर के नेतृत्व में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रार्थना की। इसी तरह आरएनए टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैरी क्रिसमस डे का पर्व परंपरागत रूप से हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक डा.पीके सिंह व प्राचार्य डा.शीला सिंह के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्र भाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। जिसका शीर्षक बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ सुनिश्चित किया गया। जिसमें विद्यालय के सभी छात्र–छात्रओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेंट जेवियर्स वर्ल्ड स्कूल पट्टीनरेंद्रपुर खुटहन में क्रिसमस–डे हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। संता क्लाज की वेशभूषा में छात्रों ने एक–दूसरे को उपहार देकर आपसी प्रेम, सहयोग व सौहार्द को मजबूत बनाए रखने का संदेश दिया।

मजदूरों का बकाया है 25 लाख

संवाददाता, जौनपुर । मनरेगा मजदूरों का जिले में 25 लाख रुपये बकाया है। आधार कार्ड व खाता संख्या का मिलान न होने की वजह से काफी समय से श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिल सकी है। बक्शा ब्लाक में सबसे अधिक 15 लाख रुपये बाकी है। सीएम के भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिये जाने के बाद जहां प्रशासनित कवायद तेज हो गई है वहीं श्रमिकों में भी मजदूरी मिलने की आस जग गई है। इसके बाद देरी होने पर कार्रवाई की जद में एपीओ समेत अन्य कर्मचारी व अधिकारी आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब मजदूरों के हित में कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया है। इसमें प्रदेशभर में मनरेगा के तहत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए 15 दिन की समय सीमा तय कर दी है। इससे अधिक विलंब होने पर श्रमिकों को क्षतिपूर्ति प्रतिदिन के हिसाब से संबंधित अफसरों के वेतन से काटकर दी जाएगी। कैबिनेट के फैसले का बाद प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है। देखा जाय तो बक्शा ब्लाक में मनरेगा मजदूरों को जहां 15 लाख रुपये की देनदारी है, वहीं में चार लाख रुपये का बकाया है। इसके अलावा मुंगराबादशाहपुर में दो लाख 63 हजार व खुटहन में एक लाख 59 हजार रुपये बाकी है। इसी तरह सोंधी ब्लाक में मनरेगा मजदूरी का दो लाख रुपये बाकी है।

भुगतान न होने को लेकर तकनीकी वजह भी बताई जा रही है। महराजगंज ब्लाक के खजांची रमेश का कहना है कि सर्वर में आयी खामी की वजह से भुगतान भुगतान नहीं हो पाया। मनरेगा के तहत कार्य कर रहे कुछ श्रमिक ऐसे भी हैं, जिनका अभी तक आधार बैंक खाते से नहीं जुड़ सका है। ब्लाकों में तैनात एपीओ को चाहिए कि वह ऐसी दिक्कतों को प्राथमिकता पर दूर कराएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा भी ऐसी तकनीकी खामियों को नजरअंदाज करने की वजह से दिक्कत बढ़ती जाती है।

यह बकाया आधार व खाता संख्या न मिलने की वजह से हुआ होगा। संबंधित ब्लाकों से जानकारी मंगाकर भुगतान कराया जाएगा। व्यवस्था में बदलाव के बाद अब भुगतान में देरी न होने को लेकर संबंधित कर्मचारियों संग बैठक कर जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद भी यदि भुगतान को 15 दिन से अधिक वक्त लगा तो कर्मचारी का वेतन निश्चित तौर पर काटा जाएगा।

शौचालय न बनाने वाले सात लाभार्थियों को नोटिस

बदलापुर (जौनपुर)। नगर पंचायत के वाडरें में बने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का बुधवार को डूडा के परियोजना अधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालय न बनाने पर सात लाभार्थियों को नोटिस भी दिया। कहा कि यदि 15 दिन में शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ तो धनराशि की वसूली की जाएगी। परियोजना अधिकारी सबसे पहले वार्ड नंबर 11 में पहुंचे। यहां करमा देवी, उर्मिला, रेखा, सुरसत्ती आदि लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण तो कर दिया गया है। शौचालय किसी ने नहीं बनाया है। सबको नोटिस देते हुए 15 दिन में बनवाने के लिए कहा अन्यथा दी गई धनराशि की रिकवरी किए जाने की चेतावनी दी। इसके अलावा तमाम लाभार्थियों ने आवास तो बनवा लिया है लेकिन दीवारों को प्लास्टर नहीं कराया है। जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्लास्टर कराने के लिए कहा।श्री वर्मा ने लाभार्थियों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह निश्शुल्क है। किसी को कदापि पैसे न दें। सीधे मेरे या नपं कार्यालय से संपर्क कर लाभ लें। डा. महेंद्र कुमार, उमेश सरोज, अंकुर, शशि, स्वप्निल सिंह, डूडा के अवर अभियंता आदि रहे।

!! शिक्षित महिला !!
Website : www.jaybajrang.org
!! शिक्षित समाज !!
Email : jaybajrangmm@rediffmail.com

जय बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
(सम्बद्ध–वी0ब0सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर)
मुँगरा बादशाहपुर,जौनपुर (उ0प्र0)
प्रवेश प्रारम्भ

बी0ए0– (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, प्रा0इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, राजनीति विज्ञान, संगीत)
एम0ए0– (हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान)
बी0एस0सी0– (प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित)
बी0एड0– (कला एवं विज्ञान वर्ग)
डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0)

अध्ययन केन्द्र–उ0प्र0राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
(एस–213) शान्तीपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद

मोबाइल नं0–
7398144409 , 9451117446
डॉ0घनश्याम मिश्र
संस्थापक/प्रबन्धक

सरकारी योजनाओं में ग्राम प्रधान का खेल

सुरेरी। गरीबों के लिए बनी सरकारी योजनाएं हवा–हवाई साबित हो रही हैं। एक तरफ जहां सरकार योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, उन्हें आवास, शौचालय, राशन, विधवा, वृद्धा पेंशन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ भ्रष्ट कर्मचारी व ग्राम प्रधान इसे पलीता लगा रहे हैं। रामपुर ब्लाक के भरथीपुर ग्राम सभा में इसका उदाहरण देखने को मिलता है। ग्रामसभा में कई गरीब परिवार आज भी ऐसे हैं जिनके पास न तो रहने के लिए छत है और न ही शौचालय। गरीब आज भी खुले आसमान के नीचे इस भीषण ठंड में अपनी जिंदगी बिताने को विवश हैं। इसके बाद भी ऐसे गरीबों का सरकारी योजनाओं में चयन नहीं हो सका। अनुसूचित जाति के रामप्रवेश, दीनानाथ, रंजीत, पंधारी, रामधनी आदि ने ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक तक कई बार चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें महज आश्वासन ही मिला। उनकी मानें तो बीडीओ को पत्रक भी सौंपा गया फिर भी नतीजा सिफर रहा। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने सभी योजनाएं अपने चहेतों के नाम कर दी। बीडीओ राजीव सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। अगर कोई भी लाभार्थी वंचित होगा तो उसका नाम शामिल कराया जाएगा।

चटकी पटरी, दो घंटे थमा संचालन

संवाददाता, सिरकोनी (जौनपुर)। वाराणसी–फैजाबाद रेलखंड के सिरकोनी स्टेशन के चौमना गांव के पास चटकी रेल पटरी की सूचना मिलते ही अधिकारियों को पसीना आ गया। बुधवार की सुबह लगभग पांच बजे वाराणसी–फैजाबाद पैसेंजर के गुजरते ही गांव निवासी निर्मल सिंह ने की–मैन को चटकी पटरी

की सूचना दी। इसके बाद तुरंत मामले की जानकारी स्टेशन मास्टर समेत अन्य अधिकारियों को दी गई। इस बीच वरुणा एक्सप्रेस को लगभग पंद्रह मिनट रोकने के बाद कासर पर पार कराया गया। दो घंटे बाद पटरी के दुरुस्त होने पर ट्रेनों का संचालन सामान्य हो सका। निर्मल सिंह सुबह टहलने निकले थे। इस दौरान उनकी नजर चटकी पटरी पर पड़ी। उन्होंने समय गवाएं बिना इसकी जानकारी संबंधित रेल कर्मी को दी और इसके थोड़ी ही देर में संदेश कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। वरुणा एक्सप्रेस के चालक को वाकी–टाकी पर सूचना देने के साथ सिग्नल रेड कर दिया गया, जिस वजह वाराणसी से लखनऊ जा रही वरुणा तकरीबन 15 मिनट खड़ी रही। थोड़ी देरबाद उसे कासन पर चलाते हुए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार कराया गया। सुबह दस बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रूट को बंद कर दिया गया। इस बीच एक मालगाड़ी को जलालगंज रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया।

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक प्रकाशक एवं प्रधान सम्पादक घनश्याम मिश्र द्वारा "जनछाया" बजरंग प्रिंटिंग प्रेस, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर से प्रकाशित

कार्यकारी सम्पादक : चंचल मिश्र
फोन : 9451117446
editorjanchhaya@gmail.com